महाराष्ट्र में 11% तक घट सकता है चीनी का उत्पादन

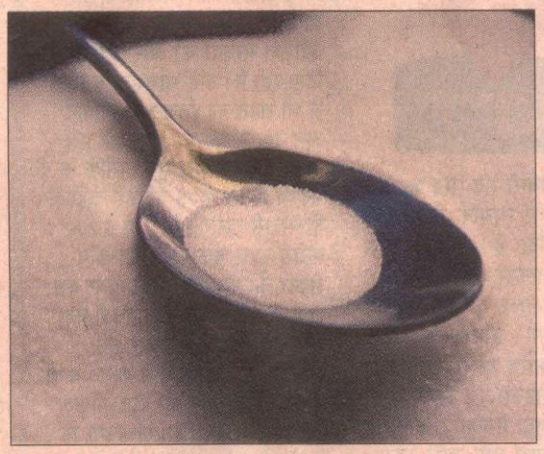

[ईटी ब्यूरो *नई दिल्ली*]

देश में सबसे अधिक चीनी तैयार करने वाले राज्य महाराष्ट्र में 2012-13 में इसका उत्पादन 11 फीसदी से अधिक कम रह सकता है। राज्य के सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटील ने बताया कि सूखे जैसी हालात की वजह से गन्ने की फसल 22 फीसदी घटने का अनुमान है। पाटील ने कहा, '2011-12 में गन्ने का रकबा 10.22 लाख हेक्टेयर था, जो 2012-13 में कम होकर लगभग 8 लाख हेक्टेयर पर पहुंच सकता है। चीनी का उत्पादन 90 लाख टन से कम होकर लगभग 80 लाख टन रहने की उम्मीद है। गन्ने की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती होगी।' राज्य में सहकारिता विभाग चीनी उद्योग को नियंत्रित करता है।

प्रोडक्शन में कमी

- महाराष्ट्र में गन्ने की उपलब्धता घटने से चीनी का उत्पादन 90 लाख टन से कम होकर लगभग 80 लाख टन रहने की उम्मीद है
- चीनी मिलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार नियमों को कड़ा करने पर विचार कर रही है। पेराई का काम शुरू करने से पहले लाइसेंस लेना जरूरी होता है

विभाग ने चीनी मिलों के लिए केन डेवलपमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया है क्योंकि अगले सीजन में गन्ने की कमी होने की आशंका है। 2011-12 के सीजन में 125 सहकारी और 51 निजी मिलों ने चीनी का उत्पादन किया था। अगले सीजन में निजी चीनी मिलों की संख्या में 10 का इजाफा होना तय है जिससे मिलों की कुल संख्या 176 से बढ़कर 186 हो जाएगी। पाटील ने बताया, 'पेराई की क्षमता पिछले वर्ष 4 लाख टन प्रतिदिन थी, जो इस वर्ष बढ़कर 5.5 लाख टन हो गई है।'

चीनी मिलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार नियमों को कड़ा करने पर विचार कर रही है। चीनी मिल को पेराई का काम शुरू करने से पहले इसके लिए लाइसेंस लेना होता है। सरकार इस लाइसेंस को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिल द्वारा किए गए प्रयासों से जोड़ने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र में गन्ने का औसत उत्पादन 81 टन प्रति हेक्टेयर का है। इस मामले में देश में तमिलनाडु पहले स्थान पर है, जहां प्रति हेक्टेयर 103 टन गन्ने का उत्पादन होता है। इसके बाद 89 टन के साथ कर्नाटक का नंबर आता है। पाटील के मुताबिक, 'हम अनिवार्य करेंगे कि प्रत्येक चीनी मिल केन डेवलपमेंट के लिए एक अलग डिवीजन बनाए। हमारा उद्देश्य उत्पादन को 100 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाने का है।'